

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
बर्डजलास - पीयुष समारिया, आई.ए.एस.

भरण पोषण अपील संख्या-41/2022
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर-2022/53

अपीलांत	बनाम	रेस्पोंडेन्ट्स
निजामुदीन पुत्र श्री अहदम खां, उम्र 69 वर्ष जाति मुसलमान सिपाही (शेरानी) निवासी कादरी कॉलोनी, मेड़तासिटी तहसील मेड़ता जिला नागौर (मोबाईल नम्बर-9772215321)		1. नदीम पुत्र निजामुदीन 2. नईम पुत्र निजामुदीन जातियान मुसलमान सिपाही निवासी मेड़तासिटी तहसील मेड़ता जिला नागौर

निर्णय

दिनांक 02/05/2022

1-अपीलान्त ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट मेड़ता द्वारा माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत दर्ज प्रकरण संख्या-02/2020 निजामुदीन बनाम नदीम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 21.12.2021 से व्यथित होकर दिनांक 28.01.2022 को यह अपील पेश की है। अपीलान्त की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

2- उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्त ने बहस में कथन किया कि अपीलांत ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 के तहत रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध प्रस्तुत कर यह प्रकट किया कि अपीलांत, रेस्पोंडेन्ट का पिता हैं और रेस्पोंडेन्ट, अपीलांत के जायन्दा पुत्र हैं, अपीलांत 67 वर्षीय वृद्धा, बीमार व सहाय व्यक्ति हैं। अपीलांत के साथ दिनांक 02-06-2018 को शाम 6.30 बजे रेस्पोंडेन्ट व इसके साथ में अन्य मुलजिमान ने मिलकर मारपीट कर जिससे अपीलांत लव लूहान होकर बेहोश हो गया। जिसका मुकदमा भी अपीलांत की ओर से पुलिस थाना मेड़तासिटी में दर्ज करवाया। जिसके मुकदमा नं. 218/2018 अंतर्गत धारा 323, 354/34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में दर्ज करवाया। जिसमें पुलिस ने गहनता से अन्वेषण कर रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में पॉक्सो कोर्ट मेड़तासिटी में चालान भी पेश किया। अपीलांत उक्त मारपीट से घायल हो गया, जिस पर अपीलांत को अजमेर हॉस्पिटल में ईलाज हेतु रैफर किया गया। तत्पश्चात् अजमेर से जयपुर हॉस्पिटल ईलाज हेतु रैफर किया गया। जहां पर अपीलांत को करीब 7-8 दिन बाद में होश आया। उक्त घटना से अपीलांत का एक हाथ व एक पैर ने काम करना बंद कर दिया अर्थात् अपीलांत लकवाग्रस्त हो गया। अपीलांत मानसिक रूप से भी बहुत कमजोर हो गया हैं तथा अपीलांत की सोचने समझने की स्थिति भी बहुत कम हो गई हैं। अपीलांत का एक हाथ व एक पैर तथा दिमाग काम कम करने से अपीलांत कमाने खाने में असमर्थ हो गया। अपीलांत के पास जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं हैं। रेस्पोंडेन्ट अपीलांत के जायन्दा पुत्र हैं। रेस्पोंडेन्ट अपीलांत से सख्त अदावत, रंजिश व दुश्मनी रखते हैं। अपीलांत के वृद्धावस्था का नाजायज फायदा उठाते हैं। अपीलांत कमाने खाने का मोहताज हो चुका हैं। अपीलांत उठने, बैठने, चलने, फिरने व खाने कमाने में असमर्थ हैं। रेस्पोंडेन्ट, अपीलांत से प्राप्त सम्पति का उपयोग व उपभोग कर रहे हैं तथा अपने आवास व निवास के लिए उपयोग में ले रहे हैं और रेस्पोंडेन्ट सं. 1 नक्शा नवीस का कार्य करता हैं, रेस्पोंडेन्ट सं. 1 का डेगाना में नक्शा नवीस का कार्यालय स्थापित हैं, एवं कुशल व अच्छा व होशियार नक्शा नवीस हैं, मकान, दुकानें, प्लॉट, प्लानिंग आदि समस्त प्रकार के कार्य करता हैं। रेस्पोंडेन्ट सं. 1 उक्त कार्य से प्रतिमाह 60,000/- रुपये आसानी से कमा लेता हैं। रेस्पोंडेन्ट सं. 2 भी रेस्पोंडेन्ट सं. 1 के साथ में कार्य करता हैं व मकान बनाने का कुशल व अच्छा कारीगर तथा ठेकेदार है। रेस्पोंडेन्ट सं. 2 मेड़ता डेगाना तथा आस पास के गांवों में मकान बनाने सम्बन्धित ठेका लेता हैं और रेस्पोंडेन्ट सं. 1 व 2 के अधीनस्थ 20-30 मजदूर प्रतिदिन कार्य करते हैं। इस प्रकार रेस्पोंडेन्ट सं. 2 के कर्मचारी भी प्रतिमाह 60,000/- रुपये इस प्रकार रेस्पोंडेन्ट दोनों मिलकर प्रतिमाह 60,000+60,000=1,20,000/- रुपये आसानी से कमा लेते हैं। किन्तु अपीलांत की कोई आय नहीं हैं। जिससे अपीलांत के भरण पोषण हेतु रेस्पोंडेन्ट को आदेश दिया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक हैं। रेस्पोंडेन्ट बदनियति पर उतारू हैं और



जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

अपीलांट का भरण पोषण नहीं कर रहे हैं। जिससे अपीलांट बिल्कुल बेसहारा हो गया है और ईलाज के अभाव में मृत्यु होने की सम्भावना हो गई है। अपीलांट अत्यन्त वृद्ध, बीमार, निर्धन व असहाय व्यक्ति हैं। अपीलांट के ईलाज हेतु अभी भी दवाईयां चलती हैं, अपीलांट बी.पी., शुगर व लकवे की स्थाई बीमारी से ग्रस्त हैं। अपीलांट को अपने ईलाज व भरण पोषण हेतु रूपयों की सख्त आवश्यकता है। रेस्पोडेन्ट का वैधानिक व नैतिक कर्तव्य है कि वह अपने पिता यानी अपीलांट को भरण पोषण की राशि अदा करें। श्रीमान अधीनस्थ न्यायालय ने नगरपालिका मण्डल मेड़तासिटी को पत्र भेजकर अपीलांट की जायदाद के सम्बन्ध में सूचना चाही, जिस पर कार्यालय नगरपालिका मण्डल मेड़तासिटी ने दिनांक 25-08-2021 को श्रीमान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस प्रकार की रिपोर्ट प्रेषित की कि अपीलांट के नाम से मेड़तासिटी में किसी प्रकार की अचल सम्पत्ति नहीं है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के उक्त आवेदन को प्रार्थना पत्र की दिनांक से स्वीकार नहीं करते हुए केवल मात्र आदेश की दिनांक 21-12-2021 से यह आदेश प्रदान किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 पृथक पृथक रूप से 3-3 हजार रुपये अपीलांट को अदा करें। जिसके विरुद्ध अपीलान्ट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

2(1)—अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से देय होना था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 21-12-2021 से लागू करने में कानूनी एवं वाकियाती गलती की है। जबकि कानून की यह मंशा है कि वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण के सम्बन्ध में उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने की दिनांक से स्वीकृत होना चाहिए।

2(2)—अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट से 10-10 हजार रुपये प्रतिमाह की मांग की है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र 3-3 हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया है, जो कम किया है। जो 10-10 हजार रुपये प्रतिमाह नहीं करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की है।

2(3)—अपीलांट के नाम से मेड़तासिटी में व मेड़तासिटी के बाहर किसी प्रकार की कोई अचल सम्पत्ति नहीं है, अपीलांट ने अपने जीवनकाल में दो शादियां की थी और दोनों को अलग-अलग बंट देकर अपीलांट ने अपने कर्तव्यों का पालन किया, रेस्पोडेन्ट के पास में रहवासी पक्का मकान है, जो अपीलांट के द्वारा दिया गया है, जिसमें रेस्पोडेन्ट परिवार सहित निवास करते हैं, रेस्पोडेन्ट युवा, नौजवान है, सक्षम है तथा कुशल व अच्छे नक्शा नवीस व ठेकेदार है। रेस्पोडेन्ट की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। रेस्पोडेन्ट का अच्छा व्यापार है, रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 प्रतिमाह 1,20,000/- रुपये आसानी से कमा लेते हैं, जबकि अपीलांट वृद्ध व बीमार होने के कारण कमाने खाने में असमर्थ है, इसलिए अपीलांट को रेस्पोडेन्ट से 10-10 हजार रुपये प्रतिमाह भरण पोषण के रूप में दिलाये जाने न्यायोचित है।

2(4)—अपीलांट वृद्ध होने से उसकी आंखों की रोशनी भी अच्छी नहीं है और बीपी, शुगर तथा लकवे से ग्रस्त होने के कारण व बीमार हो जाने के कारण अपीलांट ड्राईविंग करने में असमर्थ हो गया है। इसलिए अपीलांट अपने जीविकोपार्जन के लिए रेस्पोडेन्ट पर निर्भर है।

2(5)—योग्य अदालत मातहत ने परिस्थितियों को ठीक तरह से नहीं समझा है तथा पत्रावली पर उपलब्ध जुबानी व दस्तावेजी साक्ष्य का सही रूप से विवेचन नहीं करने का कथन करते हुए अपीलान्ट ने अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलांट को उसके भरण पोषण हेतु 10,000-10,000/- रुपये प्रतिमाह प्रार्थना पत्र प्रस्तुति की दिनांक से अदा करने का रेस्पोडेन्ट को आदेश दिये जाने का निवेदन किया है।

3—रेस्पोडेन्ट्स ने अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि अपीलान्ट प्रार्थी ने विरुद्ध रेस्पोडेन्ट्स अप्रार्थीगण के एक आवेदन धारा 5 माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिकरण अधिकारी, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मेड़ता के समक्ष भरण पोषण दिलाने हेतु पेश किया कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के पुत्र है। प्रार्थी वृद्ध है जिनकी उम्र 67 वर्ष है। प्रार्थी के साथ अप्रार्थीगण ने दिनांक 02-06-2018 को मारपीट की जिससे प्रार्थी बेहोश हो गया। जिसका मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। उक्त घटना से प्रार्थी लकवाग्रस्त हो गया व मानसिक रूप से कमजोर हो गया है तथा जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थी से सख्त अदावत, रंजिश व दुश्मनी रखते हैं। प्रार्थी के बुढ़ापे का नाजायज फायदा उठाते हैं। अप्रार्थीगण, प्रार्थी से प्राप्त सम्पत्ति का उपयोग कर रहे हैं और अप्रार्थीगण दोनों प्रतिमाह 60,000/- रुपये आसानी से कमा लेते हैं। किन्तु प्रार्थी की कोई आय नहीं है। अप्रार्थीगण बदयान्ति पर उतारू है और प्रार्थी का भरण पोषण नहीं कर रहे हैं। जिससे प्रार्थी बिल्कुल बेसहारा हो गया है और भूखे मरते मृत्यु होने की संभावना हो गई है। प्रार्थी अत्यन्त वृद्ध, बीमार व असहाय व्यक्ति है प्रार्थी के ईलाज हेतु अभी भी दवाईयां चलती है, प्रार्थी बी.पी. शुगर, व लकवे की बीमारी से ग्रस्त है। प्रार्थी को अपने ईलाज व भरण पोषण हेतु रूपयों की सख्त आवश्यकता है। जिस पर अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 ने अपना जबाब पेश किया। तत्पश्चात् अधि. न्यायालय द्वारा बहस सुनी जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक



जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

स्वीकार करते हुवे दिनांक 21.12.2021 को आदेश जैर अपील पारित कर दिया। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलान्त द्वारा गलत एवं मिथ्या तथ्यों पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

3(1)—वृद्ध माता पिता के भरण पोषण के अधिनियम 2007 के अनुसार वरिष्ठ नागरिक अथवा माता पिता जो अपने स्वयं के अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पत्ति से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है वे ही इस अधिनियम के तहत आते हैं। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो दस्तावेज प्रस्तुत हुवे उससे अपीलान्त इस अधिनियम के तहत आवेदन करने का अधिकारी ही नहीं था, क्योंकि अपीलान्त निजामुद्दीन के नाम का राशन कार्ड (बारकोड) संख्या-110801500237, उपभोक्ता संख्या 00896 जो नगर पालिका मण्डल मेड़तासिटी से जारी हो रखा है, जो निजामुद्दीन के नाम से जारी हो रखा है, उसमें अपीलान्त निजामुद्दीन की उम्र 55 वर्ष दर्ज है, यदि अपीलान्त निजामुद्दीन की यह उम्र सही है तो वह वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में नहीं आता है। जबकि प्रार्थना पत्र में निजामुद्दीन ने अपनी उम्र 67 वर्ष बतलाई है तथा अपीलान्त निजामुद्दीन ने न्यायालय के समक्ष सही तथ्य व सच्ची बातें पेश नहीं की है, सच्चाई को छुपाते हुए अपनी दूसरी शादी को व दूसरी पत्नी व दूसरी शादी से पैदा हुई संतानों को छुपाते हुए झूठ बोलते हुए न्यायालय के समक्ष, न्यायालय को गुमराह करते हुए यह गलत व झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है, क्योंकि अपीलान्त निजामुद्दीन ने करीबन 25 वर्ष पूर्व ही रेस्पोजेन्ट नदीम व नईम व उनकी माता को नेगलेक्ट/ त्याग करके दूसरी शादी नूरजहां से कर ली है तथा अपीलान्त निजामुद्दीन की इस दूसरी शादी से उसके दो लड़के और दो लड़कियां उत्पन्न हुई है, जिनका नाम साहिना, इरलामुद्दीन, इजाज व सानिया बानों है। यह सभी तथ्य न्यायालय से छुपाकर गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है। क्योंकि अगर आज निजामुद्दीन की उम्र 67 वर्ष है, तो उसके इन दोनों लड़के इरलामुद्दीन की उम्र 26 वर्ष है व इजाज की उम्र 23 वर्ष हो चुकी है तथा साहिना की उम्र 28 वर्ष व सानिया बानों की उम्र 18 वर्ष हो चुकी है तथा अपीलान्त निजामुद्दीन ने जब से यानी 25 वर्ष पूर्व से शादी से लेकर आज तक उसका यह परिवार उसके साथ रह रहा है और निजामुद्दीन व उसके दोनों पुत्र कमाते है और अपना परिवार 25 वर्षों से चला रहे हैं, इस प्रकार अपीलान्त निजामुद्दीन असहाय बिल्कुल नहीं है, उसका परिवार पूरा उसके साथ है तथा इन 25 वर्षों से लेकर आज तक अपीलान्त निजामुद्दीन अपनी दूसरी पत्नी नूरजहां व अपने बच्चों का भरण पोषण यानी इन सबका दवाई, पढ़ाई, लिखाई, खाना पीना, रहना, कपड़े इत्यादि सभी का खर्च उक्त निजामुद्दीन आज तक वहन करता आ रहा है। इसलिए अपील अपीलान्त खारिज किये जाने योग्य है।

3(2)— करीबन 25-30 वर्ष पूर्व अपीलान्त निजामुद्दीन ने रेस्पोजेन्ट नदीम व उनकी माता हाजरा को दहेज की डिमाण्ड करते हुए व मारपीट करते हुए जब रेस्पोजेन्ट नदीम की उम्र लगभग 1 वर्ष थी तथा रेस्पोजेन्ट नईम जब अपनी माता के गर्भ में था, तब मारपीट करते हुए व दहेज की डिमाण्ड करते हुए निजामुद्दीन ने इनको घर से बाहर निकाल दिया था, तब से लेकर आज तक अपीलान्त निजामुद्दीन ने रेस्पोजेन्ट नदीम व नईम व उनकी माता हाजरा को नेगलेक्ट/त्याग रखा है तथा आज तक उसने रेस्पोजेन्टस् का पिता होने का फर्ज व नैतिक व कानूनी दायित्व एक दिन भी नहीं निभाया है तथा आज तक उनकी पढ़ाई, लिखाई, दवाई, कपड़े इत्यादि पर एक रुपया भी खर्च नहीं किया है। रेस्पोजेन्ट नईम व नदीम को तब से लेकर आज तक उनकी माता हाजरा ने ही भरण पोषण किया है व पालन पोषण किया है, उनको पढ़ाया लिखाया है, उनकी बीमारी, दवाई, कपड़े, लत्ते इत्यादि का सभी का पालन पोषण उनकी माता हाजरा ने करके रेस्पोजेन्टस् को इतना बड़ा किया है। रेस्पोजेन्ट की माता ने अपीलान्त निजामुद्दीन के विरुद्ध धारा 498-ए आईपीसी का मुकदमा भी दर्ज करवाया था व रेस्पोजेन्ट व उनकी माता ने धारा 125 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र अपने भरण पोषण हेतु अपीलान्त निजामुद्दीन के विरुद्ध सिविल न्यायालय मेड़ता में दिनांक 04-08-1998 को पेश किया था, जिसमें अपीलान्त निजामुद्दीन के बयान भी दिनांक 26-08-2002 को न्यायालय में हुए थे, जिसमें निजामुद्दीन ने अपने बयानों में यह स्वीकार किया है कि "हाजरा मेरी पत्नी है, नदीम व नईम मेरे पुत्र है, यह तीनों ही मेरे साथ नहीं रहते हैं। मैंने दूसरी शादी कर ली है, इसलिए यह मेरे साथ नहीं रहते है। इसके बाद न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र में दिनांक 28-11-2008 को यह आदेश दिया है कि अपीलान्त निजामुद्दीन रेस्पोजेन्टस् नदीम व नईम व उनकी माता को 500-500/- रुपये के हिसाब से कुल 1500/- रुपये प्रतिमाह अदा करें। परन्तु अपीलान्त निजामुद्दीन ने उक्त न्यायालय की अवहेलना करते हुए आज तक रेस्पोजेन्ट व उनकी माता को 1/- रुपया भी अदा नहीं किया है। उक्त राशि से बचने के लिये ही अपीलान्त ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बदयान्तिपूर्वक ढंग से सम्पूर्ण तथ्यों को छुपाते हुवे आवेदन पेश किया था तथा अब अपीलान्त ने हस्तगत अपील पेश की जो खारिज किये जाने योग्य है।

3(3)—अपीलान्त निजामुद्दीन ने रेस्पोजेन्ट नदीम, नईम व उनकी माता हाजरा को उक्त प्रकार से दहेज की डिमाण्ड करते हुए मारपीट करते घर से बाहर निकाल दिया, नेगलेक्ट कर दिया, त्याग दिया, उसके



पश्चात् भी अपीलान्त निजामुदीन व उसके परिवार वालों ने कई बार रेस्पोजेन्ट नदीम, नईम व उनकी माता हाजरा के साथ कई बार मारपीट भी की है, जिनके मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनमें से एक फौजदारी प्रकरण सं. 102/2013, (75/2011), सरकार बनाम निजामुदीन वगैराह भी हुआ है, जिसमें निजामुदीन व उसके परिवार वालों ने रेस्पोजेन्ट नदीम, नईम व उनकी माता हाजरा के साथ मारपीट की है, जिसमें श्रीमान अति, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता ने विचारण कर अपीलान्त निजामुदीन व उसके परिवार वालों को दोषी माना है।

3(4)—अपीलान्त निजामुदीन ने एक वाहन टाटा लोडिंग गाड़ी नं, आर जे 19जी डी 2057 भी ले रखा है, जो अपनी दूसरी पत्नी नूरजहां के नाम से ले रखी है, जिसका संचालन निजामुदीन स्वयं ही करता है तथा उक्त वाहन से ही अपनी दैनिक मजदूरी भी करता है।

3(5)—रेस्पोजेन्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में जबाब आवेदन पेश किया उसके पैरा सं. 4 से 8 में अपीलान्त निजामुदीन की सम्पत्तियों एवं उसके आय के स्रोत के संबंध में सम्पूर्ण तथ्य अंकित किये तथा उसके संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश की, जिसके अनुसार भी अपीलान्त स्वयं के भरण पोषण के लिए सक्षम है। अपीलान्त द्वारा प्रत्येक रेस्पोजेन्ट की प्रति माह आमदनी 60,000/-रुपये होने एवं रेस्पोजेन्ट का जिस प्रकार से काम धन्धा होना बताया है, अपीलान्त का यह कथन पूर्णतया गलत एवं मिथ्या है। बल्कि रेस्पोजेन्ट के इतनी कमाई नहीं है। रेस्पोजेन्ट मजदूरी आदि करके छोटी-मोटी कमाई करते हैं, जिनसे उनका गुजर बसर ही हो पाता है।

3(6)—वर्ष 2018 में रेस्पोजेन्ट्स की माता हाजरा द्वारा भरण पोषण की बकाया राशि की वसूली हेतु कुर्की की कार्यवाही की गई, तब रेस्पोजेन्ट मात्र 2000/-रुपये जमा करवाये तथा शेष राशि न्यायालय में अथवा रेस्पोजेन्ट व उनकी माता को नहीं देना पड़े, इस बदनियति से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश किया है।

3(7)—उक्त प्रकार से अपीलान्त निजामुदीन अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी दूसरी बीवी नूरजहां व अपनी संताने साहिना, इस्लामुदीन, इजाज व सानिया बानों के साथ पिछले करीबन 25 वर्षों से रह रहा है तथा अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, अपीलान्त निजामुदीन के पास बहुत सारी सम्पत्तियां भी है, जिनके विद्युत कनेक्शन भी निजामुदीन के नाम से हैं, जिनको उसने किराये पर दे रखी है तथा वह स्वयं ड्राईवरी का कार्य करता है, अपीलान्त बिल्कुल भी असहाय नहीं है, सम्पूर्ण रूप से स्वस्थ है तथा उक्त प्रकार से सही व सत्य तथ्यों को छुपाकर न्यायालय को गुमराह करते हुए झूठे कथन करते हुए अपनी दूसरी शादी, दूसरी बीवी व संतानों को छुपाते हुए गलत रूप से गलत व झूठा प्रार्थना पत्र पेश किये जाने का कथन करते हुए अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील को निरस्त करने का निवेदन किया है।

4—उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्त द्वारा अपने स्वयं के भरण पोषण हेतु रेस्पोजेन्टगण जो कि अपीलान्त के पुत्र हैं, के विरुद्ध अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट मेड़ता के समक्ष माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त संबंध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-02/2020 निजामुदीन बनाम नदीम वगैराह दर्ज कर प्रकरण कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 21.12.2021 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर मुख्यतः रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 को पृथक-पृथक रूप से 3000-3000/-रुपये प्रतिमाह प्रार्थी को भरण पोषण हेतु संदाय करने का आदेश दिया गया है। अपीलान्त द्वारा उक्त निर्णय के विरुद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत कर अपीलान्त को रेस्पोजेन्ट्स से 10,000-10,000/-रुपये प्रति माह प्रार्थना पत्र प्रस्तुति की दिनांक से दिलाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया गया है। उभय पक्ष के कथनों से यह स्पष्ट है कि अपीलान्त द्वारा दूसरी शादी की गई है तथा अपीलान्त की पहली पत्नी हाजरा अपने पुत्रों रेस्पोजेन्ट्स के साथ रहती है। अधिनस्थ न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध आपराधिक प्रकरण संख्या 48/03 (104/98) नदीम, नईम व हाजरा बनाम निजामुदीन अन्तर्गत धारा 125 द.प्र.सं. निर्णय दिनांक 28.11.2008 प्रति के अनुसार भी अपीलान्त को रेस्पोजेन्ट व उनकी माता के भरण पोषण के रूप में कुल 1500/-रुपये प्रति माह अदा करने का आदेश पारित किया गया है। इसके अलावा अन्य आपराधिक प्रकरण भी अपीलान्त एवं रेस्पोजेन्ट्स व रेस्पोजेन्टस की माता के मध्य रहे हैं। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र दिनांक 15.06.2019 अन्तर्गत धारा 127 द.प्र.सं. जो रेस्पोजेन्ट्स की माता व अपीलान्त की पत्नी हाजरा द्वारा न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय मेड़ता के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार हाजरा द्वारा उक्त भरण पोषण की राशि बढ़ाई जाकर प्रति माह 10,000/-



जिला मजिस्ट्रेट
नोएडा

दिलाने का निवेदन किया गया है। इस प्रकार अपीलान्त व रेस्पोंडेन्ट्स के मध्य फौजदारी प्रकरण होने से अपीलान्त व रेस्पोंडेन्टगण के मध्य मनमुटाव हाना स्वाभाविक है ऐसी स्थिति में पूर्ण यकीन से यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलान्त के भरण पोषण की गम्भीर समस्या है। इसके अलावा अपीलान्त का कथन कि प्रत्येक रेस्पोंडेन्ट की मासिक आय 60,000-60,000/-रूपये होने के संबंध में जिस प्रकार से कथन किये हैं, उन कथनों को साबित करने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। रेस्पोंडेन्ट्स ने भी उनकी आय-60,000-60,000/-रूपये प्रति माह होने के अपीलान्त के कथन को अस्वीकार किया है। इसलिए प्रत्येक रेस्पोंडेन्ट की मासिक आय 60,000-60,000/-रूपये होने का अपीलान्त का कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त की सम्पत्ति के संबंध में अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मेड़तासिटी से रिपोर्ट चाही जाने पर अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मेड़ता द्वारा अपने पत्रांक 2030 दिनांक 25.08.2021 से नगरपालिका मेड़तासिटी के गृहकर व नगरीय विकास कर रिकार्ड अनुसार अपीलान्त निजामुदीन के नाम से किसी प्रकार की अचल सम्पत्ति दर्ज नहीं होना बताया है। माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का समुचित रूप से भरण पोषण करने का उनकी संतान एवं बालकों का एक नैतिक कर्तव्य है, और इसी सन्दर्भ में उक्त अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अन्तर्गत अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय जैर अपील पारित कर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 को पृथक-पृथक रूप से 3000-3000/-रूपये प्रतिमाह अपीलान्त को भरण पोषण हेतु संदाय करने आदि के संबंध में जो आदेश दिया गया है, वह उचित होने से निर्णय जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

5-अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट मेड़ता द्वारा पारित निर्णय जैर अपील को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को पालनार्थ एवं अपीलान्त व रेस्पोंडेन्ट्स को सूचनार्थ भिजवाई जावे।

6-निर्णय सुनाया गया।



(पीयूष समारिया)
जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर